Shri Ravindra Varma: Thank you, Sir. The Minister said that the damage was due to corrosion. May I know whether there is any truth in the report that this corrosion was caused by the fact that the column and compressors were tested with water instead of kerosene?

Shri Alagesan: I am not in a position to answer that particular question, but obviously I think it should not have been done.

Shri Hari Vishnu Kamath: This statement may also be circulated.

12.41 hrs.

DISCUSSION ON NEFA ENQUIRY AND MOTION *RE*: OUR DEFENCE PREPAREDNESS—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion on the statement laid on the Table of the House by the Minister of Defence on the 2nd September, 1963, regarding NEFA Enquiry and the motion by Shri Bhakt Darshan and Shri Raghunath Singh. Both are taken together. The time allotted was five hours. 15 minutes have already been taken and so four hours and 45 minutes remain. Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Nath Pai (Rajapur): I wish to make a very humble submission to you with regard to the time allotted to this debate. In view of its importance, I would very much urge with you that the whole of tomorrow be allotted for this. I think it seems to be the consensus of opinion in the House that the matter is too serious to be dealt with in this way—and we will be doing a lot of injustice to those who are concerned with it and we may be giving an impression that we do not take this matter much too seriously. Of course, we are also hard-pressed for time. But feel that the debate has to spill over to tomorrow, and I request that greater time may be allowed for the debate.

Shri Daji (Indore): I also rise to say a few words in the same connection. Looking to the business that is shown on the Order Paper—the Motion on the public sector undertakings and the discussion on the University Grants Comission report and so on—we would like to be enlightened as to whether we are prepared to continue with these matters tomorrow also and take up the rest on Monday or not.

Mr. Speaker: There is no question of sitting on Monday. The House decided that we will sit on Saturday. That is all. So, such amount of business as we can discuss will be taken up.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Today and tomorrow, we can sit up to 7 O'clock.

Mr. Speaker: If the House wishes.

Shri Daji: My submission is this. You know the motion in regard to public sector undertakings has come up after great difficulty. It is coming up just like an illegitimate child; it has been postponed from session to session. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order. That is coming. But now there is a demand that the time be extended. If the House agrees—

Some Hon. Members: Yes, yes.

Shri Daji: We may extend the session by one day.

Mr. Speaker: It is too late now. Many Members might have made their arrangements. It may cause inconvenience.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): I support Shri Nath Pai's suggestion that the time for the NEFA debate should be extended. But I would also request you to consider whether you can accommodate the discussion of the motion on the public sector in this way: If the time for the NEFA debate is extened to last till tomorrow and is concluded, and the time is arranged in such a way that it is concluded tomorrow in time, and the motion on the public sector undertakings allowed to be simply introduced, that will be good, because we can be sure that that motion would come up later. Otherwise, as Shri Daji said, it was put off from session to session and it never comes up.

Mr. Speaker: I will consider that. Yesterday, a proposal was made and again a representation has been made to me that today we might continue with this debate without any break, and the non-official business might be taken up tomorrow. Shrimati Renu Charavartty raised an objection that that should not be acceded to, because she feared that sometimes the session ends on Fridays and then the other business is taken up and so that non-official business would suffer. But this may not be taken as a precedent. If the House so desires, I have no objection. I am not particular that this might be done. Just as the House wishes, we can accommodate in that manner. I can assure hon. Members that it will not be a precedent. I am sorry that Shrimati Renu Charavartty is not here.

Shri Vasudevan Nair: It is the view of our Group that in consience we object to such a thing.

Mr. Speaker: Then I have no objection.

Shri Tyagi: The demand that the NEFA debate should be prolonged is just like crying or quarrelling over spilt milk. That matter is over. Why not take up a positive discussion?

Mr. Speaker: Order, order. Shri Prakash Vir Shastri. He has already taken 15 minutes.

Shri Nath Pai: So, the NEFA debate comes up tomorrow also.

Mr. Speaker: I cannot say; let it proceed now.

Shri Hari Vishnu Kamath: So, non-official business will be taken up today?

Mr. Speaker: Yes. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं अपने भाषण के पूर्वार्द्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग की चर्चा कर रहा था और मैंने अपनी चर्चा के क्रम में यह संकेत किया था कि युद्धों में सैनिक गुप्तचर विभाग का अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है । इस सम्बन्ध में मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि द्वितीय महायुद्ध में सैनिक गुप्तचर विभाग ने किस तरह फ्रांस से होकर इंग्लैंड की ओर बढ़ रही युद्ध की काली घटाओंका मुंह रूस की ओर मोड़ दिया था ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लेकिन हमारे देश में इस विभाग की ओर अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई। जब कि इस विषय में चीन बहुत सतर्क था। उसने हमारे देश में हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिए तरह तरह से यत्न किया है। पिछले दस बारह वर्षों से कहीं भेड़ चराने वालों की शक्ल में, कहीं भीख मांगने वालों की शक्ल में, कहीं रेस्टोरेंट और बैंक चलाने वालों की शक्ल में और कहीं राजनीतिज्ञों की भी शक्ल में उसने अपने गुप्तचर हमारे रहस्यों का पता लगाने के लिए रखे हुए हैं।

मेरी जानकारी में कुछ और बातें भी आई हैं, जब कि हमारा गुप्तचर विभाग इतनी असावधानी से कार्य कर रहा है, चीन के गुप्तचर विभाग ने किस प्रकार सावधानी के साथ पग उठाये हैं। अभी पाकिस्तान द्वारा हमारे कुछ हवाई रहस्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। मुझे पता चला है कि अब से कुछ दिन पहले ब्रिटेन, अमरीका और भारत के संयुक्त हवाई अभ्यास की जो बात चल रही थी, उसके लिए जो एक नक्शा तैयार किया गया था, हमारे किन्हीं जिम्मेदार सरकारी दफ्तरों से वह नक्शा हटाया गया और दिल्ली स्थित एक विदेशी दूतावास में लेजाकर उस नक्शे के फोटो लिए गए और फिर फोटो लेने के बाद उस नक्शे का जहां का तहां रख दिया गया। वहां जो व्यक्ति फोटोग्राफर था, वह एक भारतीय था, उसने अपनी देश भक्ति का परिचय देते हुए अपने देश की सरकार तक वह बात पहुंचाई, जिसका दुष्परिणाम उसको इस रूप में भुगतना पड़ा कि उसको उस दूतावास की फ़ोटोग्राफ्स की सर्विस से हटा दिया गया। परन्तु क्या हमारे लिये यह चिन्ता का विषय नहीं है कि इतने गुप्त रहस्य हमारे दफ्तरों से ग़ायब कर दिये जायें और इतने महत्वपूर्ण नक्शों का फोटो लेकर उनको ज्यों का त्यों वहां रख दिया जाये? इससे पता लगता है कि हमारे देश में चीन का गुप्तचर विभाग कितना सक्रिय है।

मेरी यह भी जानकारी है कि हमारे गुप्त रहस्यों को प्रकट करने में शराब भी एक बहुत बड़ी सहायक हो रही है। कुछ ऊंचे अधिकारी और ऊंचे अफसर सायंकाल क्लबों में जाकर शराब पीते हैं। उनकी इस आदत का लाभ उठा कर उनको शराब पिला कर मस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद वे अपने रहस्यों का उगल देते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम संकट काल में तो इस बात पर अवश्य प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए कि जिन अफ़सरों का सेना से सीधा सम्बन्ध है, या जो इस प्रकार के गुप्त रहस्यों से सम्बन्धित ऊंचे अफ़सर हैं, वे क्लबों में जाकर शराब न पीयें, ताकि हमारे रहस्य बाहर प्रकट न हों।

उदाहरण देते हुए दुःख होता है कि सेला क्षेत्र में हमारे गुप्त चर विभाग की निष्क्रियता का इतना दुष्परिणाम हुआ कि हमको ब्रिगेडियर होशियारसिंह जैसे उच्च

सेनाधिकारी को अपने हाथों से खाना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि संरक्षण मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात का आश्वासन दिया है कि अब वह इस विभाग की देख रेख स्वयं कर रहे हैं। यह देश के लिये संतोष की बात है, लेकिन क्या मैं नम्रता से यह पूछ सकता हूं कि इस डी० एम० आई० में, जिसकी उपेक्षा के कारण देश को इस प्रकार से लज्जित होना पड़ा और नेफा में पराजय का मुंह देखना पड़ा, डायरेक्टर से लेकर नीचे तक क्या कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है ? और क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी जान सकता हूं कि क्या डायरेक्टर आफ मिलिटरी इन्टेलीजेंस के विभाग में अभी तक यह स्थिति है कि सीक्रेट डाकुमेंट्स का अनुवाद करने के लिए कोई भारतीय अधिकारी न हो कर चीनी अधिकारी वहां पर नियुक्त हैं ? क्या मैं संरक्षण मंत्री से यह भी पूछ सकता हूं कि हमारे यहां यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में चीनी भाषा से सम्बन्धित नौकरियों के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए जो विशेषज्ञ शान्ति-निकेतन से आमंत्रित किया जाता है, वह वही व्यक्ति है, जिसका कि एक लड़का चीनी आर्मी में एक बड़ा ऊंचा अफ़सर है और क्या वह वही व्यक्ति है, जिस के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय में यह रिपोर्ट है कि उस को पीकिंग से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ? यदि यह बात सत्य है तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं भारतीय बालकों को हांगकांग में, फार्मूसा में, अमरीका या जहां कहीं भी चीनी भाषा अच्छी तरह से सिखाई जाती हो, वहां भेज कर ट्रेन किया जाता। इस प्रकार की बातों के लिए चीनी नागरिकों पर, हम क्यों निर्भर कर रहे हैं ?

संरक्षण मंत्री ने अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, उससे भी देश को सन्तोष की सांस लेने का मौका मिला है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वर्दी, बूट, हथियार, सड़क, हवाई अड्डे इत्यादि सब की उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। इससे यह ध्वनि तो अवश्य निकलती है कि देश के कुछ नेताओं ने पहले जो यह शिकायत की थी कि बर्फ के बूट उनके पास नहीं थे, गर्म कपड़े उनके पास नहीं थे, सही थी, अब सरकार उन सब की व्यवस्था कर रही है। पर मैं तो इससे भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके मस्तिष्कों का भारतीयकरण भी आप अवश्य करें। इस बात को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं केवल संकेत रूप में ही कहता हूं कि उनके मस्तिष्कों का भारतीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। एक बात यह भी है कि फौज और सेना के उच्च अधिकारियों के बीच में जो एक लम्बी खाई खुद गई है, उसको भी पाटने का यत्न रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में सम्मिलित कर लिया जाये। अंग्रेज मिलिट्री आफिसर्स अपने जवानों के साथ मिल कर फुटबाल खेलते थे, दूसरे खेल खेलते थे और जब कर्त्तव्य पर डटने का वक्त होता था तो कर्त्तव्य पालन भी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में इस पद्धति का पालन नहीं किया जा रहा है।

पर रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में इन सब से भी बड़ी तैयारी एक और है जो सबसे

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहले होनी जरूरी है। देश के असैनिक राजनीतिक नेता जो सेना की गतिविधियों का संचालन करते हैं, या फिर जिन के कंधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जिम्मेधारी है, रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के लिए आवश्यक है कि उन के मन और उनके कान जरूर मजबूत किए जाएं। इस बात को मैं अपनी ओर से न कह कर भारतीय राजनीति के कुशल नेता और जो बरसों तक यहां प्रधान मंत्री की दगल में बैठकर शिक्षा मंत्री का पद सम्भाल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके शब्दों में कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक "इंडिया विंज फ्रीडम में इसकी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधान मंत्री के कानों के कच्चेपन का लाभ उठा कर एक व्यक्ति किस तरह से उनको गुमराह करता रहा है। मौलाना ने यह भी लिखा है कि वह और सरदार पटेल दोनों बहुत सी बातों पर एक मत नहीं होते थे लेकिन इस विषय में उनकी और सरदार पटेल की एक राय थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रधान मंत्री को गुमराह करता है। रक्षा सम्बन्धी तैयारियों में इस बात को अवश्य सम्मिलित कर लिया जाना चाहिये।

अब मैं रक्षा साधन उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज तक हमारे रक्षा उत्पादन के साथ किस तरह से शर्मनाक खिलवाड़ होती रही है, उसका एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। इसका परिचय एक प्रश्न से मिल जाता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। २५-२-१९६३ को रक्षा उत्पादन मंत्री श्री रघुरमैया से पूछा गया था ईसापुर की राइफल फैक्ट्री के बारे में कि वहां राफइल बनाने का क्या अनुपात रहा है। रक्षा साधन उत्पादन मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि ईसापुर की राइफल फैक्ट्री में फौज की पक्की मांग पर राइफल बनाये जाते हैं और फौज की ओर से वहां कोई मांग नहीं आई थी, इसलिए १९५५ से इस फैक्ट्री में राइफल बनाने का काम स्थगित रहा। अब लड़ाई आरम्भ होने पर वह शुरू किया गया है। पर इसकी जगह बनता क्या रहा है, प्रश्न के उत्तर में वह भी बताया गया है। रेल गाड़ी के डिब्बों को खोलने की लोहे की चाबियां तैयार होती रही हैं, स्प्रिंग तैयार होते रहे हैं और भी दूसरी तरह की चीजें तैयार होती रही हैं। क्या हमारे लिए यह कोई शोभा की बात थी। क्या संरक्षण मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून की एम्यूनिशन फैक्ट्री में फोटो एनलार्जर तैयार किये जाते रहे हैं जबकि दुश्मन अपने कारखानों में धड़ाधड़ शस्त्र तैयार कर रहा था। तब जो प्रतिरक्षा मंत्री थे जब उन से यह पूछा जाता था कि आप बतायें कि हमारी तैयारियों का क्या हाल है तो जो उत्तर उनका उस समय होता था, उसको मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। राज्य सभा में २६ अप्रैल, को डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर एक वक्तव्य देते हुए उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था :—

"We are in the same position with regard to medium artillery and our production establishments are able to meet whatever demands the armed forces make upon them. If there was an emergency of a serious character, it is calculated that defence production should go up by ten times".

अभी संरक्षण मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस में तो उन्होंने कहा है कि उत्पादन दुगुना कर दिया गया है। पर पहले प्रतिरक्षा मंत्री का कहना यह था कि अगर सीरियस कैरेक्टर की एमरजेंसी आएगी तो दस गुना इसको बढ़ा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता क्या थी? वह बाकी आठ गुना कहां गया?

मेरी जानकारी में यह भी है कि जिस समय अमरीका में हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री एक बार गए तो हमारे कुछ हितचिन्तकों ने उन से पूछा कि आप बतायें कि आपके डिफेंस प्रोडक्शन का क्या हाल है तो गुस्से में आ कर उन्होंने कह दिया कि आप परवाह मत कीजिये, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हम कोई पोस्ट कार्ड या कोई टेलीग्राम आपके मिलिट्री हैडक्वार्टर्स में नहीं भेजेंगे। जब इन बातों की याद आती है तो कभी कभी मन इतना तिलमिलाता है और जी चाहता है कि इस षडयंत्र के घड़े को चौराहे पर रख करके फोड़ा जाए लेकिन जब यह खयाल आता है कि अगर इन तमाम बातों की चर्चा होने लगी और देश का ध्यान सीमाओं से हट गया और कोई चोट दोबारा लग गई तो नेफा की पहाड़ियों पर लगे खून के गीले छींटे हमें क्या कहेंगे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह और मेजर शैतान सिंह की आत्मा क्या हमसे पूछेगी और क्या जवाब देंगे उन हजारों विधवा बहनों को जिन्होंने अपने सुहाग चिन्हों—मंगलसूत्रों—को उतार कर के राष्ट्रीय रक्षा कोष में प्रधान मंत्री की झोली में डाल दिया था। इन बातों को सोचकर किसी बात से शत्रु को लाभ न पहुंचे जब यह खयाल आता है तो हम मन मसोस कर रह जाते हैं।

पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री भी तथ्यों को छिपाते रहे हैं। उन्होंने आटोमैटिक राइफल्ज़ के सम्बन्ध में कहा था कि ये इंग्लैंड के पास भी अभी तक नहीं थीं, इंगलेंड की फौज को भी अभी हाल में आटोमैटिक राइफल्ज़ दी गई हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इंग्लैंड की स्थिति में और भारत की स्थिति में बड़ा अन्तर है। इंग्लैंड पर अगर आपत्ति आ सकती है तो समुद्र के रास्ते या हवाई रास्ते से आ सकती है। इसलिए उसने आधुनिकतम जिन शस्त्रों का आविष्कार किया है उनमें हवाई और समुद्री शस्त्रों। के आविष्कार को प्राथमिकता दी है पर हमारी जैसी स्थिति वाले जो देश हैं, जैसे फ्रांस है, युगोस्लाविया है, जर्मनी है, मिश्र है, उनको देखें कि कितने बरस पहले उन्होंने अपनी मिलिट्री को ये आटोमैटिक राइफल्ज़ आदि दे दी थीं। अपनी भूल छिपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं कि इंग्लैंड में आटोमैटिक राइफल्ज़ भी कल दी गई हैं। मुझे खुशी है कि हमारे संरक्षण मंत्री ने यह कहा है कि हम अपनी रक्षा के के लिए शस्त्र भी लेंगे बाहर से और फैक्ट्रीज भी उनकी सहायता ले कर स्थापित करेंगे। लेकिन संरक्षण मंत्री जी, बाल्मीकी ने अपनी रामायण में लिखा है "शुभस्य शीघ्रम्", शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिये मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस हाउस में आपका वक्तव्य होने के बाद से बहुत से लोगों के पेट में दद शुरू हो गया है और बहुत सम्भव है कि वे आपके कानों में भी आ कर फुसफुसायें और कहें कि नहीं, अमुक देश से हथियार लेना हमें सस्ता पड़ेगा, अमुक देश से हथियार लेने से काश्मीर की समस्या के समाधान में आसानी हो जाएगी, उस देश से अगर हम हथियार प्राप्त करेंगे तो बहुत मुम्किन है कि चीन से उनकी सहानुभूति हट कर हमारी ओर हो जाए। इसलिए ऐसी बातों में आ कर आपका मन कहीं हिल न जाये। इस समय आपको बड़े दृढ़ रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि पीछे इन्हीं भूलों के दुष्परिणाम हम भुगत चुके हैं।

एक बात मैं मिग फैक्ट्री के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो भारत में लगने जा रही है। यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका आधा हिस्सा तो लगेगा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा लगेगा उड़ीसा में, ढांचा तो तैयार होगा नासिक में और इंजिन तैयार होगा उड़ीसा में। कहीं यह भी कोई राजनीतिक निर्णय तो नहीं है जो इस तरह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

से इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। आप इस सारी फैक्ट्री को नासिक में ही क्यों न स्थापित कर दें, इंजिन और ढांचा दोनों वहीं बनें क्योंकि आपस में अगर कोई भेद होगा, तो उसको वहीं दूर किया जा सके। महाराष्ट्र से जब उड़ीसा पहुंचना पड़ेगा तो कितना चक्कर काट कर जाना पड़ेगा? हां, अगर आप चाहें तो उड़ीसा में एक और फैक्टरी खोल दें। इस में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। एक ही विमान का एक हिस्सा एक स्थान पर और दूसरा दूसरे स्थान पर बने यह बुद्धिमत्ता की बात मालूम नहीं पड़ती है।

जांच विधि के सम्बन्ध में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जिस जांच के आधार पर आपका यह संक्षिप्त वक्तव्य हुआ है, वह जांच क्यों की गई थी, इसको भी मैं बतलाना चाहता हूं। एक वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने नवम्बर १९६२ में राज्य सभा में दिया था और उस वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने जो शब्द कहे थे, वे उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहता हूं। सबसे पहली बार उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा था:—

> "२० अक्तूबर, और उस के बाद खास तौर से जो घटनायें घटी हैं और हमारी जो पराजय हुई है उससे हम सबको बहुत धक्का लगा मुझे उम्मीद है कि इस बात की जांच होगी..

और फिर प्रधान मंत्री जी ने आगे कहा:

> "जिससे यह पता लग सके कि क्या क्या गलतियां की गई और कौन उसके लिए जिम्मेदार हैं"।

यह प्रधान मंत्री जी का अपना ही वक्तव्य है जो उन्होंने राज्य सभा में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको यह खयाल आया होगा कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है, अगर यह बात भी सामने आ गई तो बहुत मुम्किन है कि वह आंच मेरे सहयोगी तक और मुझ तक भी पहुंच न जाये, इसलिए झट उन्होंने अपनी पोजीशन को बदल कर ३१ दिसम्बर, १९६२ को एक दूसरा वक्तव्य दे दिया कि जांच का उद्देश्य भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए एक प्रकार का सैनिक मूल्यांकन करना होगा। जो पहले यह कह रहे थे पता लगायेंगे कि कौन उसके लिए जिम्मेदार था, वह ही ३१ दिसम्बर को वक्तव्य देते हैं जो सर्वथा भिन्न होता है और दुःख की बात तो यह है कि संरक्षण मंत्री ने भी उसी पद्धति का अनुसरण करते हुये १६ मार्च को लोक-सभा में यह कहा कि सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि निर्देश पदों को भी प्रकट किया जाए या नहीं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि यह जांच केवल एक सैनिक मूल्यांकन होगी और लोगों को दण्ड देने की नीयत से नहीं की जा रही है। यह उन्होंने कहा। लेकिन फिर जब उन पदों का निर्देश आगे चल कर किया गया तो वह स्पष्ट था। संरक्षण मंत्री की आत्मा में शायद यह बात चुभी होगी कि क्यों इस देश द्रोह के रहस्य को दबा कर रखा जाए, इसलिए उन्होंने पहली अप्रैल को फिर एक वक्तव्य दिया कि कुछ सैनिक अफसरों के खिलाफ यदि आरोप सिद्ध हो जायेंगे तो सरकार उन के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अब यह जो जांच रिपोर्ट पर वक्तव्य उन्होंने दिया है, इससे प्रतीत होता है कि वह बात बिल्कुल ही हटा दी गई है। मैं समझता हूं कि शायद संरक्षण मंत्री ने इस भाग को जो हटाया उसका कारण यह भी हो सकता है कि यह वक्तव्य पहली अप्रैल को दिया गया था, इसलिए उस वक्तव्य की कोई खास जिम्मेवारी नहीं है....

अध्यक्ष महोदय: क्या शास्त्री जी भी पहली अप्रैल के उस शगुण को मानते हैं?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ऐसी बात नहीं है। उनका वह वक्तव्य अंग्रेजी में था और अंग्रेज पहली अप्रैल को मानते हैं। इसलिए मुझे उसका उद्धरण देना पड़ा है। पर इस पर जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संरक्षण मंत्री ने इस सारी रिपोर्ट को हाउस के सामने रखने में एक कठिनाई यह प्रकट की है कि सुरक्षा सम्बन्धी हमारी तैयारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और हमारे कुछ रहस्य दूसरों को भी पता लग जायेंगे। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कहीं और यह घटना नहीं घटी और क्या उन्होंने इस तरह की रिपोर्टों को प्रकट नहीं किया? उदाहरण के लिये अमरीका में जिस समय मैकआर्थर पदच्युत किया गया था उस समय जो जांच हुई थी उस की सारी कार्यवाही न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित की गई थी, और फिर उसे ऐसे वक्त में प्रकाशित किया गया था जब कोरिया की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद भी दो साल तक वह लड़ाई चलती रही। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस का हमारी सुरक्षा तैयारियों पर असर पड़ेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

लेकिन मैं इस से भी आगे बढ़ कर एक बात और पूछना चाहता हूं। जैसी यह जांच रिपोर्ट है, आप सच्चाई के साथ बतलाइये कि क्या ईस्टर्न कमान्ड ने भी कोई ऐसी जांच की थी? अगर ईस्टर्न कमान्ड की ओर से जांच हुई थी तो उस में किस किस व्यक्ति पर दोष लगाये गये थे और किस किस व्यक्ति को वहां पर जिम्मेदार बतलाया गया था? यह भी आप जरूर बतलायें। मैं अपनी कल की बात को दोहराते हुए आज फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केवल सेना के अधिकारियों की ही जांच न कराई जाय, असैनिक राजनीतिक नेता जो उस समय सेना के संचालक बने हुए थे उन की भी अवश्य जांच कराई जाय। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री भी मेरी इस बात का स्वागत करेंगे क्योंकि कई बार उन्होंने इस सदन में कहा है कि गलती किसी की भी हो, वह छिपाई नहीं जानी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस में यह पता लगाया जाय कि जिस समय सेना की ओर से सड़कें आदि बनाने का सुझाव आया था तो किस की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि सड़कें बनाने की कोई जरूरत नहीं उस पर बहुत खर्च होगा और कोई लाभ भी नहीं होगा? एक ओर तो ब्रिटिश आर्मी का वह तरीका है कि उन्होंने पेशावर से जमरूद तक रेल की सड़क बनाई इसलिये कि कभी वजीरिस्तान पर मिलिटरी न भेजनी पड़ जाये, दूसरी ओर सड़क बनाने में आमदनी नहीं होगी और खर्च अधिक होगा, यह सोचते रहे। वह रेलवे लाइन हमेशा घाटे में रही पर इसे चलाये रखा। इसी प्रकार हथियार बाहर से बिल्कुल न मंगाये जायें, देश में जितनी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं व भी आराम से काम करें, आदि आदि निर्देश दे रखे थे। पर यह निर्णय सैनिक निर्णय थे या राजनीतिक निर्णय थे इन तमाम बातों का पता लगाया जाना चाहिये। मेरा तो अपना कहना इस सम्बन्ध में यह भी है कि १२ अक्तूबर को लंका जाते हुए प्रधान मंत्री ने जो हवाई अड्डे पर यह कहा था कि मैंने अपनी फौजों को आदेश दे दिया है कि जो चीनी फ़ौज हिन्दुस्तान की सीमा में घुस कर चली आई है उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाय, इस बात की भी जांच होनी चाहिये। प्रधाद मंत्री यह कहते हैं कि आर्मी आफिसर्स से पूछ कर राय दी गई, लेकिन उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री क्या कहते हैं? अभी अविश्वास प्रस्ताव पर उन का जो भाषण हुआ था उस में उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने के लिये क्या सेना से पूछा जाता है? उस आदेश के संबंध में प्रधान मंत्री का और प्रतिरक्षा मंत्री का आपस में विरोध है। इसलिये यह बात जांच की आवश्यकता रखती है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मेरी राय यह है कि असैनिक राजनीतिज्ञों की जांच करने के लिये जो कमेटी बनाई जाय उस में कोई भूतपूर्व कमाण्डर इन चीफ, जनरल करिअप्पा या जनरल थिमैया जैसा आदमी, जरूर रहना चाहिये जिस से पता लगे कि इस आदेश देने में किस का क्या सम्बन्ध था।

मैं संरक्षण मंत्री की इस बात को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नेफा की जांच पर इतना यथाशक्ति स्पष्ट वक्तव्य दिया है। उनका वक्तव्य देख कर ऐसा लगता है कि कटघरे में बन्द शेर अपनी सीमाओं में जितना उछल सकता है उन्होंने उपनी उछलने की कोशिश की है। लेकिन सारी रिपोर्ट के सामने न आने से देश में तरह तरह के संदेह व्याप्त हैं। राज्य सभा में भी पीछे इस प्रकार की एक मांग की गई थी कि देश के कुछ ऊंचे और निष्पक्ष नेताओं को यह रिपोर्ट दिखला दी जाय और वे अपनी राय इस पर दें। राज्य सभा में इसके लिये श्री गंगाशरण सिंह का नाम प्रस्तुत किया गया। मैं चाहता हूं कि राज्य सभा की ओर से श्री गंगाशरण सिंह और लोक सभा की ओर से आचार्य कृपालानी, इन दोनों को पूरी रिपोर्ट दिखाला दी जाय। अगर यह दोनों व्यक्ति अपना वक्तव्य दे दें कि नहीं यह रिपोर्ट वास्तव में ऐसी है जिस को प्रकाशित करना देश के हित में ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए एक बात यह कहूंगा कि अब तक इस युद्ध में जितने काम हुए हैं वे सारे प्रतिरक्षा के लिये हुए। डिफेंस मिनिस्टर बन कर तत्कालीन मंत्री ने काम किया। लेकिन माओ त्से तुंग की राजनीति यह थी कि लड़ाई लम्बे मोर्चे पर करो, जहां शत्रु का कमजोर मौका देखो, वहां हमला कर दो। लेकिन भारत की युद्ध नीति क्या थी? जहां से हमला हो केवल वहीं मुकाबला करो, कमजोर हो तो पीछे हटते जाओ, या फिर मरते चले जाओ, भागते चले जाओ, यहां नीति थी। हमारे सैनिकों ने डिफेंस तो थोड़ा किया, अफेंस कभी नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि १५०० मील लम्बे मोर्चे पर क्या उन का कोई भी कमजोर स्थान ऐसा नहीं था जहां से हम भी उन पर हमला कर सकते। उससे क्या इस प्रकार की स्थिति हो सकती थी? अब तक जो काम हुआ वह केवल प्रतिरक्षा का काम हुआ मैं चाहता हूं कि अब हमारे वर्तमान संरक्षण मंत्री प्रतिरक्षा से हट कर दूसरी तरह की ट्रेनिंग भी सैनिकों को दें। जिस काम को अब उन्होंने आरम्भकिया है उसे प्रतिरक्षा नहीं कहा जायेगा उस को संरक्षण कहा जायेगा। इसी लिये मैं ने अपने सारे भाषण में श्री मेनन के लिये प्रतिरक्षा मंत्री का शब्द का प्रयोग किया है और श्री चव्हाण के लिये संरक्षण मंत्री शब्द का प्रयोग किया है। इस का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि आप बचाव तो करें ही पर हमला भी जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आज के पश्चात् श्री चव्हाण प्रतिरक्षा मंत्री न कहे जायें बल्कि संरक्षण मंत्री कहे जायें। दोनों दृष्टियों से ही इस बात की जरूरत है।

अन्त में इस बात को कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। संरक्षण मंत्री जी, देश ने बड़ी नाजुक घड़ियों में अपनी रक्षा की बागडोर आप के हाथों में सौंपी है, और धीरे धीरे अब वह समय आ रहा है जिस को आपकी भी परीक्षा की घड़ी कहा जायेगा। अब अगर कहीं देश को दुबारा चोट लगी तो यह देश यह उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं होगा कि हमारे पास हथियार नहीं थे, अथवा हमें हमले की पहले से कल्पना नहीं थी। इस उत्तर को देश सहन नहीं करेगा।

मेरा अनुमान यह भी है कि अब की बार जो आक्रमण होगा उस में अक्रान्ता देश

एक नहीं, दो होंगे। पाकिस्तान के इरादे अभी से खराब हैं। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान को आगे कर के उस की कमर पर खड़ा हो कर चीन हमला करे। यह स्थिति भी आ सकती है। चलते चलते और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के पानी में कुछ ऐसा असर है कि बाहर से जो नया आदमी आता है यातो वह अपनी शिष्टता-वश अपनी बुद्धि की लगाम दूसरों के हाथ में दे देता है या यदि अधिक अक्लमन्द हो तो दूसरों के दिमाग पर हावी हो कर उनके मुंह से अपनी बात कहलाने लगता है। अब तक रक्षा कार्य में दूसरी बात ज्यादा होती रही है। एक सीधे सादे मस्तिष्क पर हावी हो कर अपनी बात उस के मुंह से उगलवाई गई है लेकिन कृपा कर के पहली बात जो मैंने कही शिष्टता के नाते से आप भी अपनी बुद्धि की लगाम किसी दूसरे के हाथ में न दें। देश की आज बड़ी आवश्यकता है स्वतन्त्र निर्णय लेने की। आप देश के प्रति वफादार रहें, व्यक्ति विशेष के प्रति वफादार न रहें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि नियम १८९ के अन्तर्गत जिस प्रस्ताव को मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसे ग्रहीत किया और स्वीकृत किया। उस को भाषा इस प्रकार है :

> "यह सभा ९ सितम्बर, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा "हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी" के बारे में किये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

मैं कल से अपने आदरणीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। उन्होंने अपनी प्रांजल और प्रभावपूर्ण हिन्दी भाषा में अपने विचारों को प्रकट किया है। उन के सम्बन्ध में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की यह उक्ति याद आती है :

> "जाकी रही भावना जैसी,
> प्रभु मूरति देखी तिन तैसी।"

नेफा की पराजयों के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी ने इस सदन के सामने रक्खा, और उस के बाद ९ सितम्बर को उन्होंने जो जानकारी से भरा हुआ वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया उस को विभिन्न दृष्टिकोणों के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। जहां तक श्री शास्त्री का सम्बन्ध है उन के प्रति व्यक्तिगत आदर रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हों ने भावावेश में आ कर जिन कड़े शब्दों का प्रयोग किया, उन से ऐसा मालूम होता है कि कई महीनों से उन के अन्दर जो ज्वालामुखी अन्दर ही अन्दर उबल रहा था उसे एकाएक फूट पड़ने का मौका मिला है। इस वक्तव्य का एक दूसरा पहलू भी है।

मैं तो समझता हूं कि नेफा की पराजयों के बारे में जो जांच कराई गई और जो उस का प्रतिवेदन यहां रक्खा गया है वह हमारे देश के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है।

मैं सब से पहले उन उच्च सेनाधिकारियों को हार्दिक बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन पराजयों की जांच की। क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अध्ययन है, उन्होंने बहुत ही निर्भयता और निष्पक्षता के साथ, विदआउट फ़ियर, बड़ी बारीकी से सारे मामले की छानबीन की। वे स्वयं आज भी सेना के अन्दर अधिकारी हैं, उन का भविष्य प्रतिरक्षा मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के हाथों में है, फिर भी उन्होंने निष्पक्षता से भरी हुई रिपोर्ट देश के सामने और इस सदन के सामने रखी

[श्री भक्त दर्शन]

—इस के लिए मैं उन की हृदय से प्रशंसा करता हूं ।

लेकिन श्रीमन्, इस से भी आगे मैं अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और अपने वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री जी को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि उन्होंने इस जांच पड़ताल का आदेश दे कर के और इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष और सारे देश के समक्ष प्रस्तुत कर के बहुत ही साहस, बुद्धिमत्ता और दूर-दर्शिता का परिचय दिया है । एक प्रकार से उन्हों ने स्वयं अपने आप का निरीक्षण किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि हमारे यहां क्या कमियां थीं, किन कमियों की वजह से हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा ताकि उन का हम बारीकी से अध्ययन कर सकें और उन भूलों से लाभ उठाएं और भविष्य के लिए ऐसी तैयारियां करें ताकि हमें फिर वह दिन न देखना पड़े । इसलिए, श्रीमन्, जहां मैं अपने प्रधान मंत्री जी और प्रतिरक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं, वहां एक बात उन का एक अनुयायी होने के नाते कहना चाहता हूं ।

नेफा सम्बन्धी रिपोर्ट के दो पहलू हैं । एक तो उस का नकारात्मक पहलू है कि हम ने जो गलतियां कीं क्या उन के लिए किसी को दंड दिया जा सकता है ? शास्त्री जी ने अपने भाषण में प्रतिरक्षा मंत्री के १ अप्रैल के आश्वासन का हवाला देते हुए मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया है । मैं समझता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री किसी कच्ची मिट्टी के बने हुए नहीं हैं । उन्हों ने कुछ ही महीनों के अन्दर अपनी दृढ़ता का पूरा परिचय इस सदन के सामने रखा है । मुझे पूरा विश्वास है कि वे और हमारे प्रधान मंत्री जी, जिन पर आज भी हमारा अचल और अटल विश्वास है, बारीकी से हर एक चीज का अध्ययन करेंगे और वे उस आश्वासन को पूरा करेंगे । मुझे इस का पूरी तरह से विश्वास है । सदन को मालूम है कि तीन व्यक्तियों पर तो पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, आखिर आप गुस्सा अब किस पर निकालना चाहते हैं ? हमारे पुराने प्रतिरक्षा मंत्री उस के कारण हटाए गए, चीफ आफ स्टाफ को त्यागपत्र देना पड़ा और कोर कमांडर साहब भी तशरीफ ले गए और उन की जगह दूसरी नियुक्तियां की गयीं । इस प्रकार तीन व्यक्ति जिन का मुख्यत: इस से सम्बन्ध था उन के हाथों से सत्ता ले ली गयी । इस के बाद जो उन के नीचे .

श्री रामेश्वरानन्द : जो और अपराधी हों उन को भी हटना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : विषयान्तर ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को समय दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : तपस्या कीजिए तपस्या ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह से यह बहस चलेगी । अगर इस तरह की आवाजें इधर से या उधर से आएंगी तो मैं नहीं इस कार्रवाई को चला सकता ।

स्वामी जी, आप विषयान्तर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अभी शास्त्री जी ने वक्तव्य दिया उस के सम्बन्ध में आलोचना की जा रही है । मैं कहता हूं कि अगर छोटा राज्य कर्मचारी अपराध करता है तो उस को जेल में बन्द किया जाता है । लेकिन अगर कोई बड़ा राज्य कर्मचारी अपराध करे तो उस को तो उस से भी ज्यादा दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि उस की जिम्मेवारी ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भाषण दे रहे हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं समाप्त करता हूं । मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी रेल में शराब पी कर बैठता है, तो वह केवल अपना ही नकसान करता है लेकिन अगर ड्राइवर शराब पी कर चले तो वह सारी रेल को ही चौपट कर करेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम को अपने प्रधान मंत्री जी और अपने प्रतिरक्षा मंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है । हम अपराधियों को दंड दिलाने के पक्ष में हैं, कम से कम मैं बड़ी नम्रता और दृढ़ता से यह कहना चाहता हूं । और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी और हमार प्रधान मंत्री जी, जिन को भी दोषी पाया जायगा उन को अवश्य दंड देंगे । पर यह भी विश्वास रिखता हूं, और हमारे सदन का भी यह दृष्टिकोण होना चाहिए, कि हम इस अवसर पर अपने नेताओं के हाथों को कमजोर न करें जबकि हम को चीन का मुकाबला दृढ़ता से करना है, और इस काम के लिए सारा देश उन के पीछे है । एक ओर अगर हम उन की टांगे खींचें और दूसरी ओर कहें कि इस कार्य को करो तो य दोनों परस्पर विरोधी बातें नहीं चल सकतीं ।

अब मैं निवदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का एक रचनात्मक पहलू भी है और वह यह है कि हम ने अपनी गलतियों के आधार पर आगे के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है । हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जी ने 9 सितम्बर को जो वक्तव्य इस सदन के सम्मुख रखा वह बहुत स्पष्ट और जानकारी से भरा हुआ है । उन्हों ने एक बड़ी कमी की पूर्ति की है । उन्हों ने सब से पहली बार इस सदन को और इस देश को अपने विश्वास में लिया है । उन्हों ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि विभिन्न दिशाओं में सरकार जनता के सहयोग से देश की रक्षा के लिए क्या-क्या तैयारियां कर रही है । इस के लिए मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्रो जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं ।

इतना कहने के बाद मुझे प्रतिरक्षा मंत्री जी क्षमा करेंगे यदि मैं कुछ रचनात्मक सुझाव उन के सामने रखने का साहस करूं । उन्हों ने अपने वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम अपनी सना को बढ़ा रहे हैं और इस के लिए वह 6 पर्वतीय डिवीजन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं । लेकिन मुझे यह जानकर कुछ निराशा हुई कि अभी तक केवल तीन डिवीजन ही बन पाए हैं और तीन के लिए तैयारियां की जा रही हैं । अभी कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि तीन और डिवीजनों की तैयारी की जा रही हैं और उन के लिए विदेशों से शस्त्रास्त्र लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । प्रतिरक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो तीन डिवीजनों का समाचार निकला है ये उन 6 डिवीजनों में से तीन हैं या उन के अतिरिक्त तीन और डिवीजन बनाए जायेंग । अर्थात्, मैं जानना चाहता हूं कि कुल 9 डिवीजन बनाए जायेंग या 6 ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी विवरण में बताया गया है जो एक हाई आल्टीट्यूड वारफयर स्कूल है उस में सैनिकों की संख्या दुगनी कर दी गयी है । यह उत्साहवर्धक बात है, लेकिन लद्दाख से ले कर नेफा तक जो हमारी ढाई हजार मील लम्बी सीमा है और जिस की रक्षा के लिए हम सात, आठ, नौ डिवीजन तैयार कर रहे हैं, मेरा अपना अनुमान है कि इस अवस्था में एक ट्रनिंग स्कूल से काम नहीं चल सकता । इस के लिए तो हर क्षेत्र में एक एक नया ट्रेनिंग स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि सैनिकों को पहाड़ों की लड़ाई का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा सके ।

[श्री भक्त दर्शन]

सैनिकों की भरती के बारे में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि :

Our performance has been more than satisfactory.

लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मेरे पास इस तरह की रिपोर्टें हैं कि अभी भी भरती के दफ्तरों से हजारों नवयुवक, जो उत्साही हैं, जो देश के लिए मरने को तैयार हैं, और जो हर तरह से भरती के योग्य हैं, निराश हो कर वापस जा रहे हैं क्योंकि उन को भरती नहीं किया जा रहा है। विशेष कर जिन लोगों का पर्वतीय इलाकों में इस काम का पेशा है उन को वापस जाना पड़ रहा है। गोल्डस्मिथ ने एक जमाने में स्विटजरलैंड के बारे में कहा था, जिस का अनुवाद श्री श्रीधर पाठक ने अपने शब्दों में इस प्रकार किया है :

रण में भरती हो कर लड़ना
यही यहां की खेती है।

पर्वतों के लोगों को, जिन का तिब्बत से सीधा सम्बन्ध रहा है, भरती के दफ्तरों से निराश हो कर वापस जाना पड़ रहा है। मैं यह बात कोई स्थानीय संकुचित-नेरो परोकियल—दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। अगर हम को कुछ ही महीनों में ६ से ९ डिवीजन पर्वतीय सेना तयार करनी है तो माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि चीनी तो इन्तिजार करने वाले नहीं हैं कि हम अपनी तैयारी कर लें उस के बाद वे आक्रमण करें। शत्रु तो हमेशा अपने प्रतिपक्षी की कमजोरी का लाभ उठाने की प्रतीक्षा में रहता है। तो हमें भी इन्तिजार करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं। मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग जिन को सेना में काम करने की परम्परा रही है, जिन में इस काम के संस्कार पड़े हुए हैं, उन को भरती नहीं किया जाता और उन को भरती के दफ्तरों से निराश लौटना पड़ रहा है। मैं फिर दुहरा दूं कि मैं यह सुझाव कोई संकुचित दष्टिकोण के कारण नहीं दे रहा हूं। अगर हम पर्वतीय युद्ध के लिये सेना तैयार करना चाहते हैं तो हम को इन क्षेत्रों के लोगों को अधिक लेना चाहिए।

नेफा सम्बन्धी रिपोर्ट में एक सब से बड़ी बात यह कही गई है कि हमारे सैनिक जो कि बड़ी विकट परिस्थितियों में लड़े हैं और पहले कई सफलतायें प्राप्त की थीं, उन को नेफा में असफलता मिलने का कारण यह था, कि इन को उस क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई होती थी, वे अपने को वहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना सके। लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं, जिन को पानी पीने के लिए भी एक मील नीचे उतरना पड़ता है और जो उस क्षेत्र की ऊंची चोटियों में अपने पशुओं को चराते हैं उन को इस क्षेत्र में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पहले जो भारतीय व्यापारी तिब्बत से व्यापार करने जाते थे, वे हैवी स्नो बूट पहन कर नहीं जाते थे, वे साधारण गरम कपड़े पहन कर जाते थे क्योंकि उन को उस वातावरण को सहने का अभ्यास होता था, उन में स्टमिना होता था। तो मेरा निवेदन है कि अगर हम पर्वतीय डिवीजन बनाना चाहते हैं तो मेरे सुझाव पर अवश्य ध्यान दिया जाये।

श्रीमन्, अफसरों की भरती के बारे में माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी ने कहा है कि और अफसर तो उन को काफी तादाद में मिलते हैं लेकिन इंजीनियरों व डाक्टरों के बारे में उन को निराशा हुई है। इस के लिए कुछ उपाय करने का उन्हों ने स्वयं उल्लेख किया है, और मुझे आशा है कि कुछ समय में डाक्टरों और इंजिनियरों की जो कमी है वह बड़ी मात्रा में दूर हो जायगी। लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं यहां पररखना चाहता हूं। नेफ़ा के बारे में जो रिपोर्टें मिली हैं, जिन्हों ने आंखों देखा हाल वहां का बताया है, चीन से जो लोग वहां युद्ध के मोर्चे से लौटे हैं, उन से बात करने का मुझे कुछ अवसर मिला। मैं इस परिणाम

पर पहुंचा कि ग्रामतौर से हमारे सैनिकों ने कोई गलती नहीं की। उन की वीरता में कोई कमी नहीं थी कमी अधिकांश मात्रा में हमारे ग्रफसरों की रही है। अब इस बात पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता कि इन लोगों ने क्या ग़लतियां कीं लेकिन कमज़ोरियां उन की तरफ से ज्यादा जान पड़ीं। अब तक क्या होता आया है ? चाहे वह खड़कवासला का इंस्टीच्यूट हो चाहे नेशनल डिफेंस एकेडेमी देहरादून हो, उन के अंदर पबलिक स्कूल्स और कालिजों के पढ़े हुए बड़े परिवारों के लड़के ही लिए जाते हैं, एक तरीक़े से विलासिता में जिन का जीवन बीता है, ऐसा न भी कहा जाय तब भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि ग्रारामतलबी में जिन का जीवन बीता है, अंग्रेज़ी में जो गिटपिट कर सकते हैं, अच्छे कपड़े धारण कर सकते हैं, पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, बड़े अफ़सरों के लड़के होते हैं उन की ही वहां पूछ होती है और पहले तो हालत यह थी कि वह पलटन में भरती इसलिए भी होते थे कि सलाम करने को मिलता था और अच्छी पत्नी भी मिलती थी। विवाह रूपी बाज़ार में ऐसे लड़कों का भाव भी ऊंचा होता था। ग्राम तौर पर ऐसे लड़के ही उन फौजी स्कूलों में जगह पा पाते थे। लेकिन जब वास्तविक लड़ाई ग्राई तब मालूम पड़ा कि वे कितने गहरे पानी में हैं ? हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय जरा इस पर बारीक़ी से विचार करें। वे स्वयं एक एसे प्रान्त के रहने वाले हैं जिस ने शिवाजी सरीखा हमारे देश का रक्षक उत्पन्न किया। वे शिवाजी के वंशधर हैं, उन के उत्तराधिकारी हैं। मेरा उन से अनुरोध है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं उन से यह आशा करता हूं कि वह नई नीति का अवलम्बन करेंगे।

श्रीमन्, मैं दो, तीन बातें फ़ौजी अफ़सरों की भर्ती के बारे में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत से ग्रजुएट्स, बहुत से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास नौजवान फौज में भर्ती हैं और वह इस आशा में भरती हुए थे कि बाद में चल कर उन को

अफ़सरी का मौक़ा मिलेगा। लेकिन मेरे पाठ इस तरह की रिपोर्टें हैं कि इन में से जो १०० आदमी गये थ तो उन में से केवल दस आदमी लिये गये। मैं इस के लिए यह सुझाव देना चाहता हूं कि फ़ौज में इस समय जो नौजवान काम कर रहे हैं अगर वह बेसिकली शिक्षा की दृष्टि से क्वालिफ़ायड हैं तो सब से पहले आप उन को लीजिये क्योंकि वे अग्नि परीक्षा में से निकल चुके हैं। वह सिपाहियों का कठोर और कठिन जीवन बिता चुके हैं और वे उन आरामतलब नौजवानों से अच्छे अफ़सर साबित होंगे, आरामतलबी की अपेक्षा उन का स्टेन्डर्ड ऊंचा रहेगा और वे सफल अफ़सर सिद्ध होंगे।

एसी भी शिकायतें मिली हैं कि जिन को कि एन० सी० सी० में "सी" सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फुटबाल के कैप्टेन हैं, अच्छे तगड़े एथेलीट हैं स्पोर्ट्समैन हैं, और जोकि सैलैक्शन के लिए उपयुक्त हैं, उन को न ले कर सैलेक्शन बोर्ड पता नहीं उस का क्या स्टैन्डर्ड सैलेक्शन का रहता है कि वह दुबले-पतले लोगों को चन लेता है। अब मैं कोई दोष नहीं देना चाहता लेकिन ऐसा हो रहा है। मुझे यहां तक बताया गया है कि स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह बातें हैं कि ऐसे लोग जोकि बिलकुल हर तरीक़े से फिट थे, उन को निराश होकर जाना पड़ा। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो एन० सी० सी० में काम करने वाले हैं, जो स्पोर्टसमैन हैं उन का सेलक्शन अलग हो और जनरल कैटेगरी में उन को शामिल न किया जाय। अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे और हर तरह से योग्य आदमी मिल सकेंगे।

श्रीमन्, अफसरों की भरती के बारे में अभी जैसा कि मैं ने शुरू में निवेदन किया था कि अंग्रेज़ी को वहां पर बहुत महत्व दिया जा रहा है। एक दिन यहां पर भी जब श्री रघुनाथ सिंह रक्षा बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को उठाया था। प्रधान मंत्री जी

[श्री भक्त, दर्शन]

उस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने शायद उस समय कुछ दिलचस्पी दिखलाई थी; लेकिन वह दिलचस्पी शायद वहीं समाप्त हो गई। मुझे अभी तक यह पता लगा है कि सेलेक्शन बोर्ड में इस पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, जिसकी कि वजह से हमें अच्छे कैंडीडेट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं प्रतिरक्षा मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज़ी का इतना ही मोह है तो पहले उन का सेलेक्शन कर लीजिये उस के बाद उन को अंग्रेज़ी की ट्रेनिंग दे दीजिये। जब उन्हें कमीशन मिल जाय तब उन का अंग्रेज़ी का ज्ञान बढ़ाने के लिए स्पेशल कोर्स उन को दे दीजिये लेकिन केवल अंग्रेज़ी के कारण वे अफ़सरी में जाने से वंचित रह जांय, मैं समझता हूं कि यह न्यायपूर्ण नहीं होगा।

श्रीमन्, हम उन अपने मित्र देशों के बड़े आभारी हैं जिन्होंने कठिन परीक्षा के अवसर पर, विपत्ति के अवसर पर हमारी सहायता की। श्रद्धा से हमारा हृदय, हमारा मस्तक, उन के सामने झुक जाता है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जो विवरण हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने दिया उस से कुछ चित्र स्पष्ट मालूम नहीं होता है। अब हमारे रक्षा मंत्री जी का एक वाक्य इस सम्बन्ध में यह है कि "संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार ने जितनी सहायता का वायदा किया था उस का आधे से अधिक भाग अब तक प्राप्त हो चुका है और बाक़ी का बहुत बड़ा भाग शीघ्र ही मिलने की आशा है।" फिर आगे वह कहते हैं कि "इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने जो सहायता देने का वचन दिया था उसका महत्वपूर्ण भाग हमें प्राप्त हो चुका है।" अब यह गोल चीज़ हमारी समझ में नहीं आती। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जीके सामने व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। वे यह नहीं कह सकते कि हमें कितने टैंकों की आवश्यकता है, कितनी मशीनगनों की आवश्यकता है, यह मैं मान सकता हूं। इन आंकड़ों को देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कम से कम यह तो बतलाने की कृपा करें कि अपनी आवश्यकताओं का हम ने क्या अंदाज़ा लगाया है? दूसरा पहलू इस का यह है कि हमारे जो केवल अपने ६ पर्वतीय डिवीज़न हैं, उन को ही नये औज़ार और हथियार नहीं देने हैं बल्कि हमें तो अपनी सम्पूर्ण सेना को ही कुछ वर्षों के अन्दर अन्दर सब तरह से अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित करना है। उन को सब तरह के आवश्यक साज सामान से लैस करने का एक व्यापक कार्यक्रम हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री महोदय हमारे सामने कम से कम यह तो बतलायें कि जो १०० का हम ने एक लक्ष्य निश्चित किया था कि इतनी हमें आवश्यकता है, उस में से ५० मिले, २५ मिले, एक-तिहाई या एक-चौथाई, अब तक उन में से कितना प्राप्त हो चुका है और कितना हमें अभी और मिलने की आशा है? मैं यह देख रहा हूं कि हालांकि इस को दस महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक वार्त्तालाप जारी है। अभी बातचीत हो रही है। अभी हमारा डेलीगेशन मास्को से लौटा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के इस उत्तर से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन से जो उत्तर मिला उस से उत्साह बढ़ता है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वे इस सम्बन्ध में कुछ और प्रकाश डाल सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्रीमन्, मैं इस सदन के उन सदस्यों में से हूं जोकि पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारे अपने देश के अन्दर ही अस्त्र शस्त्रों और अन्य फौजी सामान का उत्पादन होने लगे।

13.28 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

कुछ आर्डिनेंस फैक्टरियों को पिछले दिनों मुझे देखने का अवसर मिला। मुझे यह

देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ वर्ष पहले हमारी ग्रार्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो शिथिलता ग्रा गई थी वह ग्रब दूर हो गयी है। चीन ने हमें झकझोर कर के हिला दिया है ग्रौर जगा दिया है। उस का धक्का हमारी ग्रार्डिनेंस फैक्टरीज़ पर भी पड़ा है। ग्रभी कुछ दिन पहले हमारे संसद भवन में जो छोटी सी प्रदर्शिनी की गई थी उस से भी हम को काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुग्रा, ग्रात्मविश्वास भी पैदा हुग्रा कि हमारे देश के ग्रन्दर कुछ सामग्री का उत्पादन होने लगा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बतलाया है कि इस बीच में हमारा उत्पादन पहले से दुगना हो गया है। सैमी ग्राटोमैटिक राइफल्स का जो उत्पादन है यह भी सफलता का एक बड़ा भारी द्योतक ग्रौर चिह्न है। लेकिन मेरा ग्रपना ख़याल यह है कि ग्रभी तक सैमी ग्राटोमैटिक राइफल्स नमूने के तौर पर ही शायद् बनी हैं। ग्रभी हमारा परीक्षण सफल ही हुग्रा है। उसको बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों, लाखों की तादाद में बना सकें ग्रौर उन से ग्रपने तमाम सैनिकों को सज्जित कर सकें, उस स्टेज में हम ग्रभी नहीं पहुंच पाये हैं। उधर प्रयत्न करने की ग्रावश्यकता है।

श्रीमन्, यह जो ग्रांकड़े दिये जाते हैं कि हमारी ग्रार्डिनेंस फैक्टरीज़ का उत्पादन दुगना हो गया है उस के बारे में मैं रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कुछ भ्रमपूर्ण भी है क्योंकि जो ग्रांकड़े हमें दिये जाते हैं उन के ग्रन्दर जो इम्पोर्टेड कम्पोनेंट्स हैं, जो कल पुर्जे बाहर से ग्राते हैं उन को भी पूरे तरीक़े से सम्मिलित कर लिया जाता है हालांकि उन का देश में उत्पादन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं कि शक्तिमान ट्रक्स बनाये जा रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि कितने प्रतिशत कल-पुर्जे विदेशों से ग्रा रहे हैं ग्रौर कितने ग्रपने देश में बनने लगे हैं इस के बारे में स्पष्ट रीति से ग्रांकड़े नहीं दिये जाते हैं। यही बात निशान जीप के बनाने के बारे में लागू होती है। निशान जीप जापान की एक फर्म के सहयोग से हमारे देश में बनाई जा रही हैं। इस के बारे में भी साफ़ तौर से यह ग्रांकड़े देकर नहीं बतलाया जाता है कि उसके लिए कितने कल पुर्जे ग्रादि विदेश से मंगाये जा रहे हैं ग्रौर कितने ग्रपने देश में ही बनने लगे हैं। ट्रैक्टर्स की कहानी यह है कि समूचे के समूचे ट्रैक्टर्स जापान से मंगा लिये गये ग्रौर उन को दंडकारण्य एथोरिटी को दे दिया गया ग्रौर दूसरे लोगों को दे दिया गया। हालांकि ग्रधिकांश हिस्सा उन का बाहर से ग्रा रहा है लेकिन ग्रार्डिनेंस फैक्टरीज़ के उत्पादन में उन को भी शामिल कर लिया गया ग्रौर इस तरह से बतला दिया गया कि उत्पादन वहां पर काफ़ी ग्रधिक बढ़ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रांकड़े बढ़ाये भी जा सकते हैं ग्रौर रबड़ की तरह खींचे भी जा सकते हैं लेकिन वास्तविक तथ्य क्या है इस पर वे गहराई से जाने की कृपा करें।

श्रीमन्, दो, तीन फैक्टरीज़ में मुझे जाने का ग्रवसर मिला। मैं उन के नाम इस समय नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे यह देख कर बड़ी निराशा हुई कि ग्रभी तक पिछले महायुद्ध के ज़माने में जो मशीनें लगाई गई थीं वही पुरानी घिसी पिटी मशीनें चली ग्रा रही हैं। यह ठीक है कि उन से हम २४ घंटे काम कर रहे हैं। तीन-तीन पारियों में काम चल रहा है, यह सब ठीक है लेकिन उन से कितना उत्पादन हो सकता है ग्रौर कितनी तेज़ी से हो सकता है इस पर स्वयं विचार किया जाय। रक्षा मंत्री महोदय ने एक इशारा भी किया है कि उन के रिप्लेसमेंट करने का कार्यक्रम शायद् बनाया गया है।

लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि जो ६ नई फैक्टरियों की स्थापना के बारे में निश्चय किया गया था उसकी प्रगति से मुझे थोड़ी निराशा होती है। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री जी ने एक्सप्लोसिव्स की फैक्टरी के बारे में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बतलाया

[श्री भक्त दर्शन]

था कि चार साल पहले उसका निर्णय किया गया था, उस का स्वरूप स्थिर हो चुका था लेकिन अभी तक चार साल के बाद भी उसका सामान आ रहा है। तो इस गति से तो काम नहीं चलेगा। हम रक्षा मंत्री जी को हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सारा देश उन के पीछे है। परन्तु मैं निवदन करना चाहता हूं कि अफ़सरों और सैनिकों की भर्ती के सम्वन्ध में और रक्षा सामग्री के उत्पादन के सम्बन्ध में वह और गहराई से, बारीकी से, दिलचस्पी लें, तब जा कर सफलता मिल सकती है।

श्रीमन्, इस से पहले कि मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूं, मैं दो-तीन छोटे सुझाव देना चाहता हूं।

आज भी हमारे जो समर-दिशारद हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, उन के दिमाग़ के किसी कोने में शायद् यह भ्रम फैला हुआ है कि हिमालय की चोटियों में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और उस का सीधा परिणाम क्या है? अभी कुछ दिन पहले इस सदन में प्रश्न करने पर प्रकट हो गया कि नेफ़ा के इलाके में कामेंग डिविज़न में जहां चीनी सेनायें पीछे हटी हैं, वहां हमारे सैनिक आगे नहीं बढ़े हैं। केवल आसाम राइफल्ज़ का वहां पर इन्तज़ाम किया गया है, जिसे हम एक तरह की मिलिटरी पुलिस कह सकते हैं। हमारे सिविल अधिकारियों ने वहां जा कर प्रशासन स्थापित कर लिया है, यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन अगर शत्रु की ओर से एक भी धक्का लगे, यदि उस की ओर से आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न हो, तो जब वहां रहते हुए भी हम उस को नहीं रोक सके, तो वहां से दो तीन सौ मील दूर मैदानों में रह कर, फ़ुटहिल्ज़ और तेजपुर में बैठ कर, कैसे हम उस क्षेत्र की रक्षा कर सकेंगे, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और इस पर बड़ी चिन्ता होती है।

इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास के उस सबक की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उस का गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उस का मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधान मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज़ के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब, आप टहलते हुए तशरीफ़ ले आइये। हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी मिलिटरी अधिकारी के दिमाग़ में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़ कर नीचे मैदान में आ कर युद्ध लड़ेंगे, तो उन को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक वात होगी—यह एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्ज़ा हो गया, तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किन्तु वहां से हम उस को कभी भी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए।

इस के बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था, तो लद्दाख़ में और पूर्व में नेफ़ा के इलाके में। मध्यवर्ती क्षेत्र में, मिडल सैक्टर में, लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन मेरा अपना अनुमान है—और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है—कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया, तो वह मिडल सैक्टर में करेगा। इस के कई कारण भी मालूम पड़ते हैं। अभी २६ अगस्त को चीन ने हमारी सरकार को बड़ाहोती के सम्बन्ध में जो विरोधपत्र भेजा है, उस से बड़ी

ख़तरनाक सूचना मिलती है । वह बड़ी चिन्ताजनक बात है और उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । चीन एक तरह से हमला करने के लिए बहाना खोज रहा है और कहता है कि इस देश के सैनिक वहां चले आ रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, कैम्प लगा रहे हैं, आदि ।

लेकिन हमारी सरकार की ओर से ४ सितम्बर को जो जवाब दिया गया है, उस से भी मुझे निराशा होती है । हमारी ओर से कहा गया कि यद्यपि पहले हम वहां पर असैनिक अधिकारी भेज दिया करते थे, लेकिन इस साल हम ने असैनिक अधिकारी भी नहीं भेजे, यानी उस इलाके को बिल्कुल उन की मर्सी और दया पर छोड़ दिया गया है । यह बात बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है । आप ने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री जी ने उत्तर दिये थे कि चीन की ओर से जो हमारी वायु-सीमा के अतिक्रमण हो रहे हैं, उन में अब उन का ध्यान मध्यवर्ती क्षेत्र पर है । ६ मई, १९६३ को टिहरी गढ़वाल जिले में छाम स्थान तक, यानी साठ मील अन्दर तक, चीन का वायुयान आया था । उस के बाद २७ मई से ले कर १ अगस्त तक नौ बार चीनी वायुयानों ने हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया और उन नौ में से सात बार ऐसे इलाकों में किया, जो कि मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ते हैं । इस से यह साबित होता है कि चीन की नज़र अब मध्यवर्ती क्षेत्र पर है । इस का कारण भी है—अगर मध्यवर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया जाये, तो दिल्ली सब से नज़दीक है । यह कारण भी हो सकता है ।

इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से यह विनम्र और ज़ोरदार निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करें और उस क्षेत्र में यथासम्भव पूरी तैयारी की व्यवस्था करें । मैं जानता हूं कि पहले की निस्बत मध्यवर्ती क्षेत्र में कुछ अच्छी तैयारियां हो रही हैं, जिन से वहां की जनता का मनोबल बढ़ा है । वहां की जनता में हज़ारों भूतपूर्व सैनिक हैं, जो लड़ना जानते हैं, जिन्होंने दो दो विश्व-महायुद्धों में नामवरी हासिल की है । वे इस बार भी सहयोग देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन असली मोर्चा तो हमारी सेना को ही लेना पड़ेगा । इसलिए इस बारे में पहले से ही सतर्कता से तैयारी होनी चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि हमारी जो पराजय हुई, उस से हमारा एक राष्ट्रीय अपमान हुआ । मैं स्वयं कांग्रेस दल के उन व्यक्तियों में से हूं, जो अपने प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी पर अटल विश्वास रखते हुए इस बात की मांग करते रहे हैं कि हमें इस से सबक सीखना चाहिए, हमें इस से लाभ उठाना चाहिए । लेकिन इस का एक पहलू यह हो सकता है कि "बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेय" । इस की एक तरकीब यह हो सकती है कि हम अपनी कामेंग डिविज़न की पराजयों पर ध्यान न दे कर, चुशूल में जो हल्दी घाटी हुई, जो महाभारत हुआ,—लद्दाख़ में हालांकि हम कुछ मील हटे, लेकिन बहादुरी के साथ और एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हुए और स्वयं नेफ़ा में वैलांग में जब हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, तो वे एक एक इंच के लिए लड़ते हुए, अपना सारा सामान वापस लाते हुए, दुश्मन को नुक्सान पहुंचाते हुए पीछे हटे,—हम अपने सैनिकों के इन कारनामों पर अधिक बल दें । मैं रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अथौरिटेटिव, अधिकारपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जाये, जिस में इस बहादुरी का और इन शूरवीरता के कार्यों का वर्णन हो । मैं देख रहा हूं कि हिन्दी और अंग्रेज़ी में नये नये प्रकाशन हो रहे हैं, नये नये ग्रन्थ निकल रहे हैं, लद्दाख़ के वीरों की कहानियां, नेफ़ा के वीरों की कहानियां, आदि और उन में बड़ा

[श्री भक्त दर्शन]

अतिरंजित वर्णन होता है । एक तरह से उन में फ़िक्शन का एलिमेंट होता है—कथा-कहानी की तरह के वे प्रकाशन होते हैं । अत: अगर सरकार की ओर से एक अधिकारपूर्ण और अथौरिटेटिव पब्लिकेशन निकाला जाये, तो उस का परिणाम यह होगा कि हम को अपनी पराजयों का ध्यान नहीं होगा, बल्कि हम को अपनी विजयों का, अपने शहीदों का और बलिदानी वीरों का ध्यान आयगा जिन्होंने अपने जीवन को आहूत किया और जो वास्तव में हमारे सम्मान के अधिकारी हैं ।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That this House takes note of the statement made on the 9th September, 1963, by the Minister of Defence on 'Our Defence Preparedness'.".

This motion as also the discussion raised by Shri Prakash Vir Shastri are before the House.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): I have studied very carefully these two statements which have been presented by the Defence Minister. But before I begin I would just like to bring to your notice that it has just been brought to my notice—I do not know whether it is correct or not—that the Defence Minister is scheduled to reply this evening at five o'clock to the debate on the same subject in the other House. If that is so, I would request the Minister through you to postpone his reply in the other House, because if he replies today to this very debate in the other House, there will be no virtue left in this debate tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: I cannot conrol the other House.

Shri Indrajit Gupta: I am appealing to you and to the hon. Defence Minister.

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): The whole thing is not in my hands. I am in the hands of the Rajya Sabha also. There also, I am not my own master.

Shri Indrajit Gupta: The purpose of the debate in that case will be lost. Anyhow, I hope he will bear my request in mind and see that something can be done.

My feeling is that if the full NEFA Enquiry Report could not be placed before the House on grounds of security, it would have been better not to place any report at all rather than give the statement which has been given to us. This statement does not add very much to our knowledge. I am rather afraid that it might provide some fresh ground for speculation and gossip, as I shall try to show later on. But I must say at the outset that this report cannot be taken as the last word on the subject. The Enquiry by the very nature of its constitution had its own ilmitations.

The main Enquiry Officer, Lt. Gen. Henderson Brooks was by virtue of his Army rank not in a position to examine personally other high commending officers who were of equal or higher rank. Therefore, this Enquiry Commission could not personally examine either the commander of the task Force, who was also a Lt. Gen. nor the then Chief of the Army Staff who was a full-fledged General. They may have submitted written reports, and no doubt, they have, but examination on the basis of written reports and personal examination are two very diffierent things. Therefore, I do not take this report—in fact, it is not the report; because I have not seen it—or the statement on the report as the last word on an investigation into this matter.

Although the Defence Minister's statement speaks of the great and inti-

mate detail of inquiry into which it has gone, I do not see how that is possible at all, when, to begin with, the Chief of the Army Staff and the commander of the task force could not be examined by the chief enquiry officer who was of the rank of Lt. Gen.

However, I am not inclined to go into much of a postmortem, as some of my other friends here are seeking to do except in so far as material is provided by this statement itself. I do not know whether this is a summary of the original report or the Defence Minister's own conclusions on the basis of the report or the Army Headquarters' conclusions on the report—I have no idea of what it is supposed to be. However, certain admissions are made in cautious language, but made nevertheless, that are within the pages of this statement itself.

The first admission made is—I am not quoting; I am paraphrasing in my own language—that the concepts of mountain warfare which the higher commanders had were wrong and need to be corrected. The second admission, which is made indirectly, is that the leadership of the army was inadequately trained, because a positive statement is made that training in leadership is the need of the moment. Obviously, it could not be the need of the moment unless the training was inadequate. The third admission is—this is, in my opinion, a very contradictory statement—that our weapons were adequate and even could match the weapons of the Chinese, the only difficulty was that because of poor logistics, communications and transport, we could not bring them at the right time to the right places where they were required. However, the admission is made that certain types of weapons such as automatic rifles and so on would have been useful if they had been available. The fourth admission made is that there was some departure—I do not know; it is very carefully and cautiously worded, but I have tried to cull it out of it at some stage by somebody from the accepted chain of command, that there was a lack of responsibility at various levels, that there was top interference by the higher echelons of army command in tactical operations of a local nature which would better have been left to local commanders on the spot. These are all contained in this statement. The fifth admission made is that the collection, evaluation and disemination of intelligence were faulty. The sixth admission made is that General Staff work and procedures were not of the quality which they should have been of. The seventh admission made—here also a statement is made which I had better read out because I do not know what exactly it purports to say—is that 'even the largest and best equipped of armies need to be given proper policy guidance and major directives by the Government whose instrument it is.' I am in full agreement with this statement. Then 'these must bear a reasonable relation to the size of the army and the state of its equipment from time to time.' These two sentences are being interpreted differently throughout the country. I would like the Defence Minister to let us know what he means to indicate by these. One interpretation is that the Government is being criticised for not having given proper policy guidance and major directives as it should have done—this is held by a wide section of the press and perhaps by some Members here. It can also be interpreted to mean that guidance was given, but the guidance was not the correct guidance perhaps because military advice was not correct. I do not know what is meant by this equivocal statement. I do not know what lessons are supposed to be drawn from this.

But one thing is certain, that whatever guidance was given, whatever policy directives were given, whether by the Government independently or by the Government acting on military advice, in so far as it relates to that statement the Prime Minister made

[Shri Indrajit Gupta]

on the 12th October giving the country the impression that the army had been ordered and was in a position, therefore, to drive the Chinese out, it was a very unwise statement to make, which was unrelated to the size of the army and the state of its equipment from time to time. Subsequent events have proved that.

The eighth admission made—this is not a very major admission—was the condition to which the famous 4th Division was reduced by reason of many of its original units having been deployed elsewhere. By 'elsewhere' I take it to mean in the palins of the Punjab to guard against the possibility of a simultaneous thrust from Pakistan.

These admissions are made. What corresponding corrective action is proposed to be taken is not very clear. Some points have been indicated in a very haphazard and unsystematic way. I would have preferred if against each of these points the corresponding course of action and remedy proposed to be adopted now had also been indicated. It is not being done in that way.

For example, about the higher command, in the other statement regarding defence preparedness, there is ample evidence that some considerable physical expansion of the army and training institutions and the number of officers being trained is taking place. But that is the very least we can expect. But regarding the quality of this training and correction of the wrong concepts etc. which are alleged to have been there, all we are told is—perhaps he cannot tell us more, I do not know—that they are "being made aware" of their shortcomings.

Then about the weapons which were claimed to be adequate though not available at the right place at the right time. We are again told of a quantitative expansion. The output of ordnance factories is being doubled. Very good. Some of the old plant and machinery, to which my hon. friend referred, is being modernised and renovated—that is good. But what is the climax of the whole thing as put forward here? The top achievement is that we have just entered the period when the production of semi-automatic rifles is commencing. When it will go into mass production, I do not know. If it does, well and good. It will be some advance on the .303 rifle, about which so much was talked about here in October-November. But my point is, so far as reports go, that the Chinese were armed not with semi-automatic rifles but with automatic rifles, not only self-loading but self-firing. And I am quite sure that if ever we have to come to accounts with Pakistan, whose indigenous defence production is probably negligible, and who will be supplied by their partners in the CENTO pact, they may very well be equipped with fully automatic rifles.

An Hon. Member: Or China.

Shri Indrajit Gupta: Yes. Therefore, the production of the semi-automatic rifles, even on an initial scale, may be a good thing, but it shows that we are far far behind the level of requirements.

Out of the proposed six new ordnance factories—this is the most alarming of all—only two can even be started now, by virtue of some assistance from the US for making ammunition in one and from the UK in another. That is all the progress that has been registered in the last nine months in regard to our claim about new ordnance factories. Our Government has only acquired land and put up buildings and arranged for water supply and so on, but now we are waiting to see where assistance will come from. We do not even know which particular factory is going to produce what; it depends entirely on what asistance we get

from some country or other. This is stated here.

About intelligence, it is stated that a major overhauling is required and will take place under the personal supervision of the Defence Minister. I am very glad. The report does not tell us anything about a point I had raised during the discussion on the demands for grants of the Ministry last April—whether it is a fact that the army command is going to be equipped with its own intelligence system, independent of the Central Intelligence Bureau of the Home Ministry, upon which we had to depend last November. There is a small sentence put here about the DMI—Director of Military Intelligence. So far as I know, the DMI's job, at least in the past, upto now, was mainly concerned with intelligence within the armed forces—some sort of a counterpart of the CID in relation to the civil. But that is not the type of military intelligence we were concerned with. I want to know whether we will go on depending on the Home Ministry's apparatus or whether the army is going to have its own intelligence, a properly organised system of military intelligence. It is not indicated.

I agree that there should not necessarily be a witch-hunt. Why should there be? But somebody was witch-hunted out of his job at that time..

Shri Ranga: Very good.

Shri Indrajit Gupta....and witch-hunts are still talked of here.

Shri Ranga: Very good.

Shri Indrajit Gupta: Even while trying to avoid any further witch-hunt, I cannot avoid making some criticism, well deserved criticism, I think, of some sectors of our high command, military command The Prime Minister, who happens not to be present here, always seems to get irritated for no particular reason if any criticism is levelled against a particular person who was the Commander of the Task Force.

Shri Ranga: His favourite.

Shri Indrajit Gupta: It has been said here, for example, about the poor quality of general staff work. Before he became the Commander of the Task Force, he was the Chief of the General Staff. Therefore, if General Staff work and procedures were of a very poor quality, it is an indirect reflection on the same gentleman. What was he doing when he was CGS?

Apart from that, he was made the Commander of the Task Force despite the fact that never in his past military record had he any spell of active service to his credit, actual active service in the field. His past, if one goes into it, is a past of dealing entirely with things which are rather in the field of the Quarter Master General, that is supplies and that kind of thing. The Chief of the General Staff is the chief post, as the Defence Minister has stated here, for co-ordinating the whole thing, long-term operational planning, legistics, transport, supplies and so on. So, during his tenure as CGS it seems that grave lapes were committed, though the matter is not stated here clearly, and when he was appointed Task Force Commander, the post of Chief of General Staff was left unoccupied. I want to know whether it is a fact or not. Why is it not mentioned here? If anything contributed to confusion and chaos, what could it be but this fact that the Chief of the General Staff was switched over as Commander of the Task Force and the post of the Chief of General Staff, which is the vital link in the whole machine, was left when the attack was taking place?

I want to know whether it was Lt. Gen. Kaul or not who advised the Prime Minister on this question of adopting the forward policy, which was reflected in that famous state-

[Shri Indrajit Gupta]

ment of the Prime Minister? He should have been in a position to know the real state of our preparedness and our military equipment and so on vis-a-vis the Chinese. Did he or did he not give this advice that we were strong enough to carry out probing movements? Was he or was he not responsible for the movement of troops from Tawang to Dhola which led to the immediate attack? We may have been lulling ourselves into complacency thinking that probing attacks would not invite a big counter-attack, but who was responsible we would like to know, because we are told here continually that somebody sitting in armchairs in Delhi sent orders there and pressurised the army command into doing something which left to itself. It would not have done. My knowledge is not that. My knowledge is to the contrary. My knowledge is that certain Generals who combine incompetence with bellicosity and have Napoleonic ambitions gave advice of this type.

Shri Ranga: They were here also.

Shri Indrajit Gupta: And if that advice was acted on unwisely, nevertheless the responsibility must be fixed on those military commanders. And I am really surprised—Shri Shastri has already mentioned it—that even before the enquiry is concluded, this gentleman is permitted to fit himself into a nice, cushy job on Rs. 10,000 a month.

Shri P. K. Deo: Shri Thirumala Rao is there.

Shri Indrajit Gupta: Is this what is supposed to be good for the morale of our jawans? I agree with the Defence Minister who has said in his statement that nothing should be done or said which is harmful to the morale of our forces, but is this good for the morale of our jawans that before the enquiry is concluded, we read in the papers that the Commander of the Task Force has landed himself in a nice job on Rs. 10,000 a month? Of course, his Napoleonic tendencies may get better room for play in the ambitious projects of the Jayanti Shipping Company. I do not know, but will the morale of the men who had to pay the price for his follies be boosted by this?

Shri Thirumala Rao (Kakinada): May I interrupt the hon. Member for a moment to say that this gentleman has nothing to do with the Jayanti Shipping Co.? It has been repeatedly contradicted, but my friend persists in his ignorance. I am sorry for it. He has nothing to do with the Jayanti Shipping Co., I once again tell him.

Shri Indrajit Gupta: Is he connected with that company?

Mr. Deputy-Speaker: He is one of the directors.

Shri Indrajit Gupta: Similarly about the Commander of the Fourth Division. I have got nothing against that gentleman, I do not know much about him either, he may have a very good record for ought I know. He may have been thoroughly justified as the local commander on the spot in thinking that discretion was the better part of valour, and that to save his men was better tactics than to die a glorious death. I do not know. He may have a hundred justifications, but I want to know whether he was ordered or not to hold the Sela position at all costs while reinforcements were being brought up behind to deal with the Chinese roadblock at Bomdila, and whether, in spite of the order, he decided to withdraw and give up the Sela position without a fight. My point is, if he acted on his own in defiance of the orders given to him, could he not have been found a better job to do than that of inculcating discipline in our youth as Director of the National Discipline Scheme? That is all I say. These things are not good for morale, anybody's morale.

We have been assured here in this House on a previous occasion that there was no interference, categorically we have been told, and I hope Shri Anthony of all people has noted it, that there was no governmental interference in tactical, field operations at any stage.

Shri Frank Anthony (Nominated-Anglo-Indians): By whom? That is untrue, absolutely untrue.

Shri Indrajit Gupta: Until evidence is produced to the contrary, we do not know.

What I wish to state here is that while we must see this thing in its proper perspective, many of my friends are so overwhelmed by the retreat of our forces, that they see only the retreat. They do not see the retreat of the aggressor.

Shri Frank Anthony: And the reason?

Shri Indrajit Gupta: Yes, we want to know the reason. Did they go back because of our superiority of arms?

Shri Frank Anthony: Because Krishna Menon was sacked.

Shri Indrajit Gupta: May I know whether the Anglo-French and Israeli troops which launched an all out military attack by sea and air on Egypt in 1956 had to retreat because of the superior military might of little Egypt? Did the Chinese have to go back from NEFA because suddenly they thought we were becoming so strong that they would not be able to advance further? The whole point is there are other forces abroad in the world, which Shri Anthony and his friends are totally ignorant of. There are forces abroad which stand for peace, democracy and progress, and those forces are strong enough today to compel aggressors to retreat or to hold back the hand of the aggressor.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): Including the Chinese Lobby in India.

Shri Indrajit Gupta: Many of the gentlemen in this House who in November last were talking about the identity of Russia and China, saying that we should never trust any of them, should be thankful today that the mighty Soviet Union has come out categorically in our defence against the Chinese aggressor, and they should reckon with this.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Russia has also said that if there is aggression against China, Russia will treat it as aggression against itself.

Shrimati Renu Chakravartty: Are we going to commit aggression against China? Is that our policy?

Shri Indrajit Gupta: You are a little bit out of date.

Mr. Philip Talbot, Assistant Secretary of State for South-east Asian Affairs of the US Government has stated only yesterday that if Pakistan and India are involved in a military conflict with each other, there will be an American response—on which side we do not know. The United States is tied by a military pact to Pakistan, please remember.

Shri Ranga: As Russia is with China.

Shri Indrajit Gupta: Therefore, I wish to say that policy is part of defence too, and my friends who see only one part of it, the weakness of the policy which led to our being in a comparative state of defence unpreparedness, do not see the other aspect also which has enabled us to isolate the aggressor and to push him back.

Shri P. K. Deo: Day dreaming.

Shri Ranga: Dange has done it by going to Moscow!

Shri Indrajit Gupta: In my opinion, the single biggest lesson which emerges out of this Report and the statement of the Defence Minister is the question of developing our self-sufficiency in defence production. Shri Prakash Vir Shastri says that we must have no inhibitions as to purchasing or borrowing or getting by way of gift all the equipment and weapons we want from various countries. We have no objection to that, but my point is that it can only be a stop gap measure, it can only be a supplementary measure to fill the gap, provided that simultaneously we are taking resolute measures to stand on our own feet and acquire self-sufficiency. Until we are able to do that, this country's defence will always be at the mercy of others.

14 hrs.

Shri Frank Anthony: Especially of the communists.

Shri Indrajit Gupta: Anybody. I do not want to be at the mercy of Shri Frank Anthony just as he does not want to be at my mercy. Let us stand on our own feet. Why are you afraid of that? (*Interruption*). Therefore, I am pointing out that this progress that is claimed, the switching over from .303 rifles to semi-automatic rifles, this sort of hesitant step—starting one or two ordnance factories—and all these things, are not adequate compared to what is required. We are actually frantically trying now to buy whatever we can from wherever we can. This famous shopping list of India's arms requirements, I regret to say, has become quite a joke in some parts of the world. If you read the western press, you will find how they joke about it. Here is the *Statesman* which I am sure Shri Frank Anthony reads very faithfully every morning —it is not a communist paper, or, has it become a communist paper?

An Hon. Member: He does not know!

Shri Indrajit Gupta: Well, I do not know. May I quote from the editorial of the *Statesman* dated 19th September, 1963?

Shri Frank Anthony: I even read the *New Age*.

Shri Indrajit Gupta: It says:

> "The eagerness of the right wing critics to get "massive aid" from the West—a phrase they first used in the dark days of November and have stuck to since—must cause some amusement in Western capitals. The reluctance is as great there as in Mr. Nehru's heart to go in for a massive involvement in a border war in the Himalayas except if another big attack by China seems more imminent to them than it does just now. Their present eagerness does not go much beyond making the arrangements already being made for receiving their help effectively, should the need for it arise; they are not willing to do much more at the moment, however great the disappointment for some people in India. Now does it seem to be desired by them (or desirable for us) that we should make an aggressive display of anti-Communism."

This is from the *Statesman* of the 19th September. Therefore, I wish to point out this. Of course, we shall buy whatever we require from wherever we can get it although it amounts to this, namely, the standardisation of our equipment is being given the go-by. Later on we will get into the ditch over questions like spare-parts. That cannot be helped perhaps. But it can only be the supplementary step. As far as aid from the west is concerned, we must remember it has very severe limitations in the fact that there are strings

attached; the fact that we have already given an undertaking that this equipment will not be used against Pakistan We have given that undertaking without which we would not have received this aid.

Shri Ranga: Nothing wrong with that.

Shri Indrajit Gupta: Also, whatever aid we get from the west, I am sure full information with regard to it can go to the potential aggressors due to the very system of military alliances within which they are. Therefore, aid has been limited mainly to transport, communication, etc. The British are *also giving aid to China, as you know, according to the papers. They are sending nuclear equipment and transport planes to China as well. Therefore, there are limitations.

Take, for example, the UAR, a smaller country than ours, much **smaller,** much weaker. What are they doing after their experience of Suez? It is reported in the papers. Their minister was here only yesterday. His statement has appeared in the press. He has said that Egypt has already built a supersonic jet factory at Halwan to which we are sending some Indian technicians also. If they can do it, why cannot we? They have got missiles which were displaced in their parade in Cairo on their independence day. They have got automatic weapons. Their minister, Mr. Salaam, said yesterday in Delhi that this is being paid for. The money for it is found by the fact that the Government of UAR has nationalised the whole of their export-import trade —85 per cent of their capital industries and 25 per cent of their domestic trade. This is how a poor, underdeveloped country gets the required finances for building up an independent defence potential, and that is what we have always been pressing for.

Of course, it is admitted that our resources are limited. Once again I want to remind the Defence Minister of the little request I had made of him last April: please fix up your priorities, but priority No. 1 is the development of our independent defence potential, for which the development of heavy industries and basic industries—everything—is essential. Without steel, without heavy foundries, without heavy forge, without alloy steel, we cannot build the kind of defence potential that we require. Therefore, all the critics who are shouting about our defence unpreparedness, and at the same time, are violent opponents of the scheme of development of heavy industries and strategic industries are wrapping themselves up in a contradiction which can only have some political motive behind it.

I conclude by saying that history is always replete with examples of the fact that the aggressor always has the initial advantage. It does not depend only on the equipment and weapons, that the defenders will be able to prevent even a single inch of their ground from being taken. The French were sitting behind their wonderful Maginot Line in 1940 and within 24 hours they found themselves routed. The Soviet army which was certainly not unprepared and which was well-equipped, had to go several hundred miles back into its own territory before the Hitler hordes, before it was able to make a come back.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): With American aid and help.

Shri Indrajit Gupta: Why does he want to stick to America? He does not want to stand on his own. (*Interruption*).

Shri Daji: More loyal than the king.

Shri Indrajit Gupta: Therefore, finally, I want to say that we should not see this thing in the incorrect perspective as though there has been disaster from which it is impossible

[Shri Indrajit Gupta]

to recover. Certainly we were very pained at what had happened, but the point is to gird up our loins and go forward on the correct lines, so that our defence system can be properly overhauled and put on its own independent footing and that alone, combined with the correct political foreign policy which has got us allies throughout the world, will enable us to guard our borders securely in the future.

Shri P. C. Borooah: (Sibsagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after hearing the previous speakers on the motion, I think that the Defence Minister's statements of 2nd and 9th September are honest and comprehensive and present an evidence of the vigorous spirit with which the Indian army is being rebuilt. The inquiry has revealed with a courageous forthrightness, for which Gen. Henderson Brook and his party deserve tribute, that in almost every aspect of leadership and organisation, the NEFA operation suffered from basic deficiencies, major among them being the failure of those in higher command to depend on the initiative of the commanders at the terrain level, inability of the army to grasp the concept of mountain warfare, and the lack of means of communications and inadequate intelligence.

Ours is a new democracy, wedded to the principles of non-violence and *Panchsheel.* We do not want a single inch of other's territory. We are prepared to do all the good to all countries whatever is possible for us. We are under the impression that we are friendly to all countries and were actually striving hard to settle our disputes with Pakistan in a congenial manner. We never anticipated that there will be any country in the world which will attack us, much less China, whose Prime Minister Mr. Chou En-lai openly, the other day when he came to New Delhi, proclaimed "*Hindi-Chini Bhai Bhai.*" These considerations came in our way of giving much importance to the strengthening of our army, which was truncated at the partition of the country, during the entire post-independence period.

The problems presented by the inquiry are no doubt formidable but the account of the defence preparations given by the Defence Minister, in his statement of the 9th September, reflects both in its spirit and content, an unconditional determination of the Government to put things right. There should be absolutely no quarrel with the manner in which Government has released the main findings of the official inquiry. They are as comprehensive as possible, consistent with the national security. Nothing can be gained from any attempt to transform the inquiry into a mischievous kind of witch-hunting. What the country needs at this time is to be reassured that the lessons of the NEFA reverses have been learnt well. To this, the answer is the Defence Minister's statement of September 9, which is an outstanding piece of document and meets the inadequacies highlighted by the inquiry report.

Having said so, I would like to make a few observations in regard to defence preparedness in my part of the country. Coming as I do from the State of Assam, I would like to say that the people of that State are not very much satisfied with the present state of affairs. During the second world war, the whole place was humming with activity like movements of vehicles, movements of troops, etc. Huge forests were converted into beautiful landing grounds in a month's time. The way it was done inspired confidence everywhere. This was the state of affairs at that time. Today again, Assam is a frontier State, but we cannot say those things now. That is why we are more concerned with what we are going to do today and tomorrow; we are not much concerned with what had happened already, except learning lessons from the past.

My first observation is about communications. Communication to NEFA is still far from satisfactory. No amount of building of roads in NEFA will be of any use, if the roads in the adjacent plains areas are not improved. Just before the Chinese aggression of October-November last year, a bridge over the Dhansiri river on North Trunk Road was damaged by flood. It remained unrepaired during the whole period of the aggression. So, transport of military equipment and military movements suffered terribly, and a great loss was sustained because they had to make a circuitous route, involving an extra distance of 100 miles, for crossing the mighty Brahmaputra, and entailing enormous delay in rushing supplies to the frontier. This year also, another bridge on the South Trunk Road in Assam has been damaged and a portion washed away. It is still under repair. As a result, the movements of military articles and civil supplies also are very much disturbed. The people are greatly suffering. I, therefore, impress upon the hon. Defence Minister that he should look into this matter; he should look into the improvement of the roads in Assam also, along with the improvement of border roads.

I may also mention in this connection about the unsatisfactory performance of the railways in that border State. Some 8 months ago, there was an attack by the Naga hostiles on a passenger train. Since then no train is running at night and the passenger and goods trains are reduced to the minimum. This has not only created undescribable difficulties for the people there, but has also affected the transport of military goods and personnel in that area. This has also acted as a source of encouragement to the Naga hostiles for carrying on their hostile activities. I, therefore, suggest that normal running of trains both day and night should be resumed forthwith and the proposed alternate track linking the important towns of Assam and away from hostile-infested areas be taken up earlier.

My second observation is that, while considering the question of augmenting our frontiers, we cannot ignore the fact that NEFA is inhabited by a small number of people, virtually separated from the rest of the country. The area is a big one covering some 35,000 square miles, with a population of only 3½ lakhs of unsophisticated people divided into different tribes, speaking differing dialects. They have been administratively and otherwise kept separated from the people of nearby plains. Such a state of affairs should not be allowed to continue.

NEFA students are still taken to China for education at the People's Institute for Minorities in Peking This should be stopped immediately. Emotional integration of the NEFA people with the people of the plains is already overdue. The people in NEFA must not be allowed to feel that they are alone in times of crisis. Already ominous reports are in the air that the Chinese spying activities are gaining ground in NEFA. There are uprisings by Daflas against the present regime and a number of our officials had been killed. Mishmis on the other side are trying to establish contacts with the Chinese. There is practically no check for the Chinese agents entering NEFA from the north. All these demand that the philosophy of NEFA should be revised. The Chinese wall raised between NEFA and Assam should be demolished and the people there should be brought closer to those in the plains. After all, it should not be forgotten that the fate of the people of NEFA is tied with the fate of the people of Assam and the neighbouring areas.

My third observation is, that Assam with NEFA, Nagaland, Manipur, Tripura and the districts of Jalpaiguri and Cooch-Bihar in West Bengal be treated as a separate unit, so far as defence preparations are concerned. We are fully aware of the fact that there is heavy concentration of troops and full-scale war preparations are

[Shri P. C. Borooah]

being made by the Chinese in the Chumbi Valley. It may so happen that one night the Chinese may suddenly attack the narrow area near Siliguri and cut off this region from the rest of the country. And, against the heavy pressure of world opinion, the Chinese next morning will agree to a proposal of amicable settlement, which India will have no way out but to accept and continue talks year after year. What will happen thereafter with Pakistan in the south and west, Naga hostiles in the east and the Mizo secessionists in the extreme south can better be imagined than described. To guard against such an eventuality, this region should be made self-supporting, so far as defence arrangements are concerned, so that they may be able effectively to resist the Chinese invaders without depending on the Centre at that time.

For this, I may be permitted, with apologies, to suggest that a full-fledged army headquarters be established in that region and a few ordnance factories set up there and more recruitment to the army be made from amongst the people of the hills and plains of the region. The population of this area is about one and a half times that of the new-born country Malaysia with an area bigger than a few of the industrially developed countries in the West.

Another dangerous development in the northern frontiers is that the Naga hostiles have been of late able to establish contacts not only with Pakistan but also with China and are receiving supplies of arms from these countries. It should be tackled with a strong hand. Last but not least, the increase in the frequency of the border incidents coupled with Pakistani infiltration into Assam and adjoining areas has been viewed by the people of that region with extreme seriousness. It will be very very wrong to assume that the Pakistani infiltrants enter Assam only for economic reasons, but there are definite indications that there is a political motive behind it. This has rendered the frontier vulnerable and I urge that this menace should not be separated from the general question of defence preparations.

Finally, Sir, the country in general and the army personnel in particular, are watching the proceedings of this august House with great interest and anxiety. Nothing should be said here which will undermine the security of the country and bring discouragement to those on whom depends the defence of the country. In all our words and deeds we should not forget, as has been very rightly said by our Defence Minister, the lonely man standing on the snow-covered mountain peak, who had dedicated his life for the cause of the country, guarding the frontier day in and day out pointing his gun towards the enemy. He should be told that the 45 crores of people of this country are behind him and he should feel secure that the 45 crores of our people will do everything for him. With this end in view, Sir, we should take part in this discussion and see that we maintain our integrity.

With these few words, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity and I wholeheartedly support the motion on our defence preparedness.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, even though we would have appreciated better had this enquiry been given to somebody other than the serving soldiers who depend for their promotion and for their service on the Government, I pay my tribute to those officers who have been entrusted with this work for the immense service they have done to this country by having completed this report in a record time and, at the same time, having brought to light some inherent mistakes in our approach and thinking in this vital problem.

Sir, I congratulate the Defence Minister for having created this

healthy precedent by giving an opportunity to this House to discuss so vital a subject which had all along been tabooed by his predecessor.

I beg to submit that the official summary of this eagerly awaited report has fallen short of our expectations. In spite of the Prime Minister's promise, an unexplainable plea has been taken for withholding the report on the ground that "information about the strength and development of our forces and their location would be of invaluable use to the enemy". Sir, no one wants any information regarding the strength and disposition of our troops. We are all anxious, as every patriotic Indian, to know on whose shoulders the responsibility of this debacle could be squarely placed. We want to know the reason for this national humiliation. The Defence Minister cannot brush aside this issue by such statements as that the intention is to derive lessons for the future and not for witch-hunting. I am not a witch-doctor, neither am I a fatalist that I reconcile everything to fate. I want to know who are the persons responsible. I do not mind if somebody is court-martialled or somebody is impeached. But, Sir, unless this is done, unless deterrent punishment is provided for the purpose who are responsible for it, we are encouraging people to run away from the battle field, we are encouraging people to run away from their responsibility and, in the long run, it will tell upon the morale of our armed forces.

From whatever material has been available to us, there can be no two opinions that the report is an admission of the failure of the Government in its primary duty to defend this country and to preserve its territorial integrity. Sir, this document is a more terrible indictment than the severest critics of the Government have ever charged it with. If you read in between the lines, if you closely study the sequence of events, you will be convinced that all the findings, all the fingers point at one person, and at only one person who was at the helm of affairs, that is, the then Defence Minister.

The report has rightly said:

> "Even the largest and the best equipped army need to be given proper policy guidance and major directives by the Government whose instrument it is."

It is an admission that so far as the NEFA defence set up is concerned proper guidance was not given, proper directive was not given at times, and this has led to this sorry state of affairs.

Let us examine the state of affairs in October, 1962. Again, more startling revelations have been made of the state of military unpreparedness, shortage of equipment, lack of proper communication lines, shortage of vehicles, lack of logistics, defect in the system of command, poor military intelligence and, above all, constant central interference in the direction of the operation.

The most shocking thing that has come to our notice is the state of military unpreparedness. The report says:

> "Our training of troops did not have a slant for a war being launched by China."

What assessment of Chinese intention could there be when while our armed forces in that altitude were being subjected to the rains of Chinese fire and mortar attack our Defence Minister was toasting "Hindi-Chini-Bhai-Bhai" at Geneva with Marshal Chen Yi by clinking the wine glass? Sir, we have been telling from these very benches from the beginning to properly understand the intention of a ruthless expansionist Communist power like China. But all our words have fallen into deaf ears. No lessons have been learnt from the trigger-happy Chinese who have been shoot-

[Shri P. K. Deo]

ing at our Indian patrols right from 1959 at Kong La and Longju up to the fateful October, 1962. Sir, the Government of India is not a Bharat Sadhu Samaj that it would be chanting shanti mantras even when it is fired upon.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): How can you think of it?

Shri P. K. Deo: Nor is it so irresponsible like any private individual or Acharya Vinoba Bhave who, can afford to indulge in occasional irresponsible stunts like sending school children to the border to change the heart of the Chinese or to arrange a peace march to Peking. After all, it is the Government of India that has to face hard realities.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Vinoba Bhave did not send any peace mission to China.

Shri P. K. Deo: I am sorry. I am speaking subject to correction. I was saying that for the Government which has to face hard realities to deal with questions in such half-hearted manner as has been done now is nothing but high treason.

We have tolerated times without number Chinese aeroplanes violating our air space. Time and again when we have asked why those intruding planes could not be shot down, even though our Canberras have been subjected to firing by Pakistani forces, some vague replies are given.

Sir, on 12th September 1959, when the discussion on the first White Paper took place, in which I had the privilege to initiate the debate, I told this House to streamline our defence forces. I still remember the words of the Prime Minister then, they are still ringing in my ears. He called us "timid", he called us "weak", he called us "panicky" and he called us "alarmists". At that time Shri Dange ....

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue tomorow. The House will now take up Private Members' business.

14.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-SIXTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg to move:

> "That this House agrees with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th September, 1963."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House agrees with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th September, 1963."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: DEFENCE OF INDIA ACT—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further discussion of Shri A. K. Gopalan's Resolution regarding the Defence of India Act.

Shi Gauri Shankar Kakkar was on his feet. One hour and four minutes are left for this Resolution. The Minister wants half an hour. How much time does Shri Gopalan want for the reply?

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): Fifteen minutes.